Already, there are necessary amenities for the passengers. As the hon. Member has stated, if it needs reconsideration, I will try to see what can be done.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: As the hon. Minister knows, the main line, the grand chord line, the Sahebganj line that runs through Shantiniketan and the narrow-gauge line from Katwa to Burdwan, all these lines and the goods trains and passenger trains, even the Rajdhani Express. run through Burdwan and terminate at Howrah, that is, at Calcutta. In the Fifth Plan period, both the passenger traffic and goods traffic will increase. In view of these facts, may I know whether the Government will take necessary steps to re-model the railway lines, the terminal facilities, from Asansol to Burdwan and from Howrah to Burdwan, whether these facilities will be increased and the Burdwan station will be re-modelled. If it is not done, then there will be discontent among the passengers and there will be dislocation of trains also. I would like to know from the hon. Minister whether in the Fifth Plan, he will take necessary steps to re-model the railway lines, the terminal facilities and re-model the Burdwan station.

SHRI L. N. MISHRA: The hon. Member has asked the same question. The importance of Burdwan is there. There is no quarrel on that point. About the provision of additional facilities, as I said, when we take up the case of other stations in the Fifth Plan, apart from what we have already decided, the case of Burdwan will also be considered in view of the points made out by the hon. Members.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Whether you are also going to declare Burdwan-Asansol as suburban section?

SHRI DEBENDRA NATH MAHATA: Will the hon. Minister be pleased to state, as he said just now that for re-modelling a railway station three conditions are necessary, that is economic viability, utility and administrative grounds, whether regarding Burdwan Station such conditions are fulfilled or not so that this Station may be included for re-modelling in the Fifth Plan?

SHRI L. N. MISHRA: Burdwan qualifies very much. It is in the thick of the colliery area. It is very important; I know. That is why I have said that I will give consideration to it.

Production of Polyethylene powders and Alcohol by Union Carbide

*794. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state.

(a) what is the capacity of Union Carbide for Low and high density Polyethylene powders,

(b) what is their actual production,

(c) have they been given any expansion of capacity recently;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) when will the Government of India's Petro-Chemical Corporation Limited begin production of low density polyethylene?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) to (e). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

PRODUCTION OF POLYETHYLENE POWDERS AND ALCOHOL BY UNION CARBIDE

(a) and (b). M/s. Union Carbide India Ltd. are licensed to manufacture 9,000 tonnes/annum of low density polyethylene. Their production during the last 3 years was as under:

1971	15,105 tonnes
1972	15,345 tonnes
1973	14,764 tonnes

(c) and (d). They have been permitted to expand their capacity for

manufacture of low density polyethylene to 20,000 tonnes/annum on account of the following considerations:

(i) The demand for low density polyethylene is expected to increase substantially in the next two years Despite the creation of substantial capacity in favour of a public sector undertaking it is expected that the demand would be substantially in excess of the likely production over the next few years.

(ii) The expansion scheme of M/s Union Carbide is expected to materialise within a reasonably short time.

(e) The Indian Petrochemical Corporation Ltd. is likely to start its production of low density polyethylene in 1976.

श्री मधु लिमये इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि लो डेंसिटी पोलीथलीन के उत्पादन की स्वीकृत शक्ति नौ हजार टन थी । 1965 के बाद यह बात मानकर भी हम चले कि 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी तो यह 11225 टन हो जाती है और 1972 में वास्तविक पैदावार 15345 टन थी । इसका साफ मतलब है कि शुरु से ही जानबूझकर अधिक मशीनरी आदि मंगाई गई थी और इस कम्पनी के द्वारा सरकार को ठगाया गया था । मैंने प्रश्न मे हाई डेंसटी पोलीथलीन के बारे मे भी पूछा है । इन्होंने इसका जवाब तक नही दिया है । यह मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर मैं जानना चाहता था कि क्या इस कम्पनी को हाई डेंसटी पोलीथलीन के लिये भी छूट दी गई थी जिसमे मफत लाल की एक कम्पनी की एकाधिकारशाही है । सबसे पहले ये इसका जवाब दे कि क्या इनको डाइवर्सिफिकेशन की छूट दी गई और उनकी जो मूल शक्ति थी उसको तो इन्होंने बढ़ाया हो, पंद्रह हजार तक बढ़ाया और उसके बावजूद भी इसको और विस्तार देने की छूट दी जा रही है, इसका इनके पास क्या खुलासा है ?

श्री शाहनवाज खां . यह सही है कि लाइसेंस्ड कैपेसिटी नौ हजार टन थी और इन्होंने 1972 में 15345 और 1973 में 14764 टन प्रोडक्शन किया । जो फुलर युटिलाइजेशन स्कीम है उसमे अगर कोई बाहर की मशीनरी या और कुछ सामान न मंगाये तो दो सो परसेंट तक खुद ब खुद उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. .

श्री मधु लिमये: जादू से हो जाता है ?

श्री शाहनवाज खां . अब इस कम्पनी को बीस हजार टन अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दी गई है । हकीकत यह है कि मुल्क में इस वक्त सिर्फ दो कम्पनियां हैं जो लो डैंसटी पोलीथलीन बना रही हैं । इस वक्त मुल्क में तीन हजार फर्में है जिनमें तीन लाख आदमी काम कर रहे हैं । वे ज्यादा तर स्माल स्केल युनिट्स है जो कि मारे मारे फिर रहे हैं और उनको माल नही मिल रहा है । बाहर से इम्पोर्ट करने की वे दरख्वास्ते देते रहते है । हम चाहते है कि ये पंद्रह हजार टन या बीस हजार या तीस हजार टन तक अपनी प्रोडक्शन को बढाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें—

श्री मधु लिमये : अगर कैपेसेटी नौ हजार टन थी तो क्या जादू से पंद्रह हजार टन उत्पादन हो गया ? कैपेसेटी को कैसे आंका जाता है ? फौरन एक्सचैंज कैसे दी जाती है ? यह सरकार है, प्रशासन है ? मैं इसका खुलासा चाहता हू । डाईवर्सिफिकेशन के बारे में भी जवाब दें ।

श्री शाहनवाज खां : डाईवर्सिफिकेशन के बारे मे जवाब यह है कि हाइई डैंसटी पालीथलीन के लिए एक ही फर्म मुल्क में है और वह मफ्तलाल की फर्म है और उनको इसकी इजाजत है। कोई दूसरी फर्म को डाईवर्सिफिकेशन के लिए अभी तक इजाजत नहीं है और न ही किसी ने दरख्वास्त दी है। लेकिन इस वक्त जरुरत है इस बात की पोलीथलीन की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा

तेजी के साथ बढ़ाया जाएं। हजारों इंडस्ट्रीज इस माल के बगैर तड़प रही है....

श्री मधु लिमये : जादू से बिना फारेन एक्सचेंज मुहैया किए हुए, बिना मशीनरी इम्पोर्ट किए हुए उत्पादन डबल हो जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : मशीनरी में कुछ आल्टरेशन करके भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । मुल्क के अन्दर भी उस में तबदीली की जा सकती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बढ़ाता है, तो बड़ी खुशी की बात है।

श्री मधु लिमये : इस का अर्थ यह है कि विदेशी कम्पनियों की लूट करने की खुली छूट दे दी गई है :

श्री शाहनवाज खां : देसी कम्पनियां भी करें। उन को खुली छूट है, उन के लिए कोई रुकावट नही है। देसी कम्पनियां न बनाये इस लिए और कोई भी न बनाये, यह पालिसी गलत है।

श्री मधु लिमये : सब सदस्य समझ गये हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। बडौदा की सरकारी कम्पनी, इंडियन पैट्रो-कैमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मे चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक लो डेन्सिटी पालिथिलीन की पैदावार शुरू होने वाली थी, लेकिन अब मंत्री महोदय कह रहे है कि उस की पैदावार और दो साल के बाद शुरू होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड का इंजीनियर्ज इंडिया लिमिटेड के साथ कोई कन्ट्रेक्ट था, जिस के अध्यक्ष एम० एस० पाठक साहब हैं, जो अभी न्यू फ्रेंड्ज को-आपरेटिव हाउस-बिल्डिंग सोसायटी के रैकेट में पकड़े गये थे, और जिन को अपना प्लाट सरंडर करना पड़ा है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी एक फारेन कोलैबोरेशन के नाम पर जान-बूझ कर इस कारखाने की रचना, बनावट, में विलम्ब किया जा रहा है, ताकि इस की पैदावार जल्दी शुरु न हों, और विदेशी कम्पनियों को अभाव का फ़ायदा उठा कर देश को लूटने, और मुनाफ़े को विदेशों में भेजने का मौका मिले।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस बात की पुरज़ोर तरदीद करता हूं कि जान-बूझ कर हमारे प्रोडक्शन में देरी की जा रही है, या रोडा अटकाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है और ऐसा सोचना भी बहुत गलत है। माननीय सदस्य ने जिन साहब का नाम लिया है—पाठक साहब का, वह हमारे देश के चोटी के इंजीनियर हैं। वह प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं और देश की मायानाज़ हस्ती हैं। उन पर ऐसी एसपर्शन कास्ट नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेस्चन है। क्या इंजीनियर्ज इंडिया लिमिटेड के द्वारा किसी फ़ारेन कोलैबोरेशन के नाम पर इस कारखाने की रचना मे बाधा डाली जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : मै बडी इनकसारी के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम अपने देश मे पेट्रो-केमिकल्ज फ़र्टेलाइजर्ज और स्टील वगैरह के सभी कारखानों में इस बात की कोशिश कर रहे है कि उन मे इन्डिजिनस पार्टस, देसी पुर्जो, की मिकदार ज्यादा से ज्यादा बढाई जाये और फ़ारेन इम्पोर्टिड पार्टस की तादाद को कम किया जाये। इस के लिए इंजीनियर्ज इंडिया लिमिटिड कोशा है। कभी कभी कोई पुर्जे मैच नही करते है, या कोई दिक्कत हो जाती है। लेकिन उन की नीयत पर शक करना गैर-मुनासिब बात है।

SHRI K. GOPAL: In the statement it is said that they mere licensed to manufacture 9,000 tonnes. (a) What is their installed capacity?

(b) The Minister said that the demand is expected to increase substantially. I want to know whether any study has been made How much it is going to increase? Is the demand going to be met from the public sector or whether the Government is going to allow only the private sector.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Very roughly the demand for low density polyethylene is approximately 45,000 tonnes at present. It is rapidly increasing and there is a tremendous demand for it from the small scale sector. As I said there are 3,000 units of them in the field and each of them is keen and anxious to expand and export their products. They are doing good work and we want to ensure that they are not starved of raw materials.

With regard to the other question, they are permitted to expand upto 20,000 tonnes.

SHRI MOHANRAJ KALINGARAYAR: As the Minister has stated, there are only two companies which are manufacturing low density polyethylene granules and he is aware and of course, every one here is aware that there is an acute shortage of polyethylene granules throughout the country. He said that the Union Carbide has been permitted to expand their production from 9,000 tonnes to 20,000 tonnes. I would like to know whether for this expansion they are going to float a new company or are they given expansion for the same old company and also I would like to know as to how much of foreign exchange is involved for importing machinery.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN. No foreign exchange would be involved and no foreign collaboration is required. It is by merely expanding the existing capacity that they can step up production to 20,000 tonnes.

नियम पुस्तकों और प्रपत्रों का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

*797. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की नियम पुस्तकों की संख्या 430 के लगभग है ;

(ख) क्या रेलवे कार्यों में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रपत्रों की संख्या 2500 है; और

(ग) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में इनके अनुवाद की वर्तमान स्थिति क्या है ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): (a) and (b). Yes Sir, this represents the position on all the Railways taken together.

(c) Total number of Railway manuals and forms translated into Hindi is 172 and 238 respectively. As regards their translation into regional languages, figures are not readily available.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मंत्री महोदय ने उन नियमावलियों और प्रपत्रों की संख्या नहीं बताई है, जो विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित किये गये हैं । मंत्री महोदय बतायें कि हिन्दी के साथ साथ विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रेलवे की नियमावलियों और प्रपत्रों के अनुवाद की स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि इन अनूदित प्रपत्रों की स्थिति यह है कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मराठी के प्रपत्र मिलते हैं और मराठी भाषी क्षेत्रों में गुजराती के प्रपत्र मिलते है ? क्या मंत्री महोदय इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जहां जिस भाषा के प्रपत्रों आदि की आवश्यकता है, वहां वे उपलब्ध हो सकें ।

श्री एल० एन० मिश्र : मेरा ख्याल है कि यह सही नहीं है कि महाराष्ट्र में गुजराती के और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मराठी के फार्म आदि भेजे जाते हैं । माननीय सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हैं । हाल ही में उस समिति की बैठक हुई थी । हमने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को उतना ही प्रोत्साहन मिलना चाहिये, जितना कि हिन्दी को और दोनों में कोई टकराव क्लेश नहीं है । हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जनता के प्रयोग में आने वाले फार्म्स आदि का अनुवाद हो ।